कितनी वृद्धि हुई है और इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 के चालू मौसम के दौरान 15 जून, 1991 तक चीनी का कुल उत्पादन 116.63 लाख टन हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी तारीख को यह उत्पादन 106.94 लाख टन था। 1990-91 के चालू मौसम के अंत तक चीनी का उत्पादन लगभग 119 लाख टन होने का अनुमान है जब कि पिछले मौसम के दौरान यह उत्पादन 109.89 लाख टन था।

(ग) और (घ) चीनी उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस वर्ष आंतरिक उपभोग हेतु खुली बिक्री चीनी की रिलीज बढ़ा दी है। जून तथा जुलाई, 1991 के प्रत्येक मास के लिए 6.25 लाख टन खुली बिक्री कोटा रिलीज़ कर दिया गया है जबकि पिछले वर्ष इन्हीं महीनों के दौरान 6 लाख टन खुली बिक्री चीनी रिलीज़ की गई थी। जून, 1991 के दौरान चीनी की खुदरा कीमतें 8 रु. 60 पैसे से लेकर 10 रु. प्रति कि. ग्रा. रही जबकि पिछले वर्ष इसी मास के दौरान इन कीमतों का स्तर 8 रु. से लेकर 9 रु. 30 पैसे प्रति कि. ग्रा. तक रहा था। प्रत्येक मास खुली बिक्री चीनी की पर्याप्त मात्रा रिलीज़ करके तथा अन्य आवश्यक नियामक उपायों द्वारा चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाएंगे।

कृषि उपज का उत्पादन लक्ष्य

21. **श्री राम जेठमलानी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1991-92 के वर्ष के लिए देश में कृषि उत्पादन का लक्ष्य 182.5 मिलियन टन निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि आगामी वर्षों के लिए कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष 3.5 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक वार्षिक उत्पादन दर में 2.8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो आगामी वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से नए उपाय किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली राम चन्द्रन): (क) वर्ष 1991-92 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 182.5 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के लिए कृषि विकास का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) सातवीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-99) में कृषि उत्पादन की संयुक्त वृद्धि दर 3.97 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, जबकि इसके मुकाबले 1949-50 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान दीर्घावधि वृद्धि दर 2.66 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

(घ) खाद्यान्नों और अन्य फसलों के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिपादित उपाय है-(1) स्थान विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र में वृद्धि (2) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के पानी और मृदा की नमी का कुशल उपयोग (3) कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता के स्तर बढ़ाने पर जोर देना और, (4) किसानों को आदानों की सप्लाई सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में करना अधिक उपज देने वाली किस्में

की खेती को लोकप्रिय बनाने और उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रचार में राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी मदद के लिए गेहूं, मक्का और कदन्नों के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, समेकित चावल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास पर योजना, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम आदि जैसे विशेष फसल प्रधान कार्यक्रम जारी रखे जायेंगे। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

अवैध भट्ठियों द्वारा इस्पात का उत्पादन

22. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1991 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "20 परसेन्ट स्टील प्रोड्यूस्ड बाई इल्लीसिट फर्नेसिज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में इस्पात-उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए निकट भविष्य में कोई कदम उठाने जा रही है, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट की प्रमुख बातों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) गौण इस्पात क्षेत्र में इस्पात विनिर्माण की लाइसेंसीकृत इकाइयों को आधुनिक बनाने तथा उनकी क्षमता 2.5 लाख मी० टन वार्षिक तक बढ़ाने की अनुमति दी गयी है। इस क्षेत्र में और अधिक क्षमता की कुछ नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है।

विवरण

मृदु इस्पात और कच्चे लोहे की मदवार तथा आकारवार वीर्घावधि मांग की बाबत एन० सी० ए० ई० आर० की रिपोर्ट की प्रमुख बातों को दर्शाने वाला विवरण

लोहे तथा इस्पात के विभिन्न उत्पादों की अनुमानित मांग :

1. तैयार मृदु इस्पात की अनुमानित मांग, जी.डी.पी. में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की परिकल्पना के संदर्भ में, वर्ष 1994-95 तक 214 लाख मी. टन और वर्ष 1999-2000 तक 292 लाख मी. टन होने की संभावना है। अनुमान है कि कच्चे लोहे की मांग वर्ष 1994-95 तक 20 लाख टन मी. तथा वर्ष 1999-2000 तक 25 लाख मी. टन तक हो जाएगी। वर्ष 2000 तक तैयार मृदु इस्पात की मांग में 6.04 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है।

2. इस्पात की चपटी मदों की मांग में 8.45 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है जबकि अचपटी मदों की मांग में 4.53 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है।

3. चपटे उत्पादों की दो मदों, शीत बेल्लित कायलों/चादरों और तप्त बेल्लित कायलों/चादरों की मांग में 9.35 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि होने की संभावना है जो सभी इस्पात मदों में सर्वाधिक है।

इस्पात की पुनर्बेलन इकाईयों की महत्वपूर्ण बातें

1. भारत में 1093 पुनर्बेलन इकाइयां हैं जिनकी कुल स्थापित वार्षिक क्षमता 210 लाख मी. टन है, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया गया है और 79,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया है।